THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI YOGENDRA MAK-WANA): (a) The three months old telephone duos outstanding as on 31-3-82 was Rs. 17.01 crores. This represents the cumulative arrears in respect of bills issued over several yeBTs upto the end of December, 1981. During the last three years, bills to the extent of Rs. 1563 crores have been issued. The aforesaid outstanding even with reference to this, works out to be less than 1.1 per cent.

(b) The figures of three months old outstanding telephone revenue as on 31st March during the last three years were as follows:

	(In crores of rupees)
31-3-80	16.68
31-3-81	16.45
31-3-82	17.01

(c) The collection of this information from the records of more than 21 lakh subscribers all over India would involve considerable clerical labour and the results expected to be achieved may not be commensurate with the labour involved.

(d) The following steps are taken for recovery of the outstanding dues:

(i) Reminding the subscribers on phone for payment.

(ii) Disconnection of the telephones if payments are not received.

(iii) Persuading the subscribers to settle the dues through personal contacts.

(iv) Litigation wherever possible and necessary.

(v) In case of Government subscribers, various departments of Central Government and State Governments are addresed at higher levels for early clearance of dues.

बिजली की आवश्यकता

872. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री अश्विनी कुमार :
श्री कलराज मिश्र :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए पृथक रूप से राज्य-वार कितनी मेगावाट-बिजली की आवश्यकता है तथा केन्द्र तथा राज्य मिलकर कुल कितनी बिजली का उत्पादन करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बिजली और कोयले की कमी के कारण उद्योग-जगत और कृषि जगत को हानि पहुंची है, यदि हां, तो क्या किसी स्तर पर इस हानि का कोई मूल्यांकन किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में कुल 3400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है जिसमें 1200 मेगावाट पन-बिजली भी शामिल है तथा देश की आवश्यकता इससे तीन गुना अधिक है तथा तीन वर्षों के पश्चात् यह इससे भी कई गुना बढ़ जायेगी, और

(घ) यदि हां, तो देश में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार की विस्तृत योजना क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत की मांग का अनुमान सारे राज्य के लिए लगाया जाता है । चूंकि विद्युत प्रणाली पर समकालिक अधिकतम मांग को ही नापा जा सकता है, अतः श्रेणीवार संघटक मांग को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है । वर्ष 1982-83 के लिए 11वें

विद्युत सर्वेक्षण द्वारा राज्यवार मेगावाट में मांग के अनुमान का विवरण (उपाबन्ध I) में दिया गया है। अप्रैल-जून, 1982 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली का कुल उत्पादन 7047 मिलियन यूनिट था तथा राज्य क्षेत्र में 22665 मिलियन यूनिट था।

(ख) विद्युत उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा पिछले वर्ष की अपेक्षा विद्युत की स्थिति काफी अच्छी है। इसके अलावा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती गई है। जिसके लिए उद्योगों पर सामान्य औद्योगिक उत्पादन में हानि के लिए विद्युत की कमी एक कारण है। लेकिन केवल विद्युत की कमी के कारण हुई हानि को आंका नहीं जा सकता।

(ग) 27700 मेगावाट की निर्धारित मांग की तुलना में देश में इस समय कुल 17000 मेगावाट उत्पादन है। 11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1985-86 में देश में विद्युत की मांग 36847 मेगावाट होने की संभावना है।

(घ) मांग और पूर्ति के अन्तर को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

(i) मौजूदा ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों से इष्टतम उत्पादन करना;

(ii) छठी योजना अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट तक उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।

(iii) फालतू विद्युत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को विद्युत का अन्तरण करना।

उपबन्ध—I

1982-83 में विद्युत की मांग

राज्य/क्षेत्र	1982-83
	(मेगावाट)
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	1084
हिमाचल प्रदेश	120
जम्मू और कश्मीर	268
पंजाब	1559
राजस्थान	1286
उत्तर प्रदेश	3621
चण्डीगढ़	61
दिल्ली	628
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	2195
मध्य प्रदेश	1675
महाराष्ट्र	3707
गोवा, दमन और द्वीय	114
दादर और नागर हवेली	2.7
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	1706
कर्नाटक	1854
केरल	912
तमिलनाडु	2444
पांडिचेरी	49
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	1576
पश्चिम बंगाल	1716
उड़ीसा	787
सिक्किम	9.2

राज्य/क्षेत्र	1982-83
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
असम . .	242
मणिपुर . .	15.3
मेघालय . .	25
नागालैंड .	12.1
त्रिपुरा . .	18.1
अरुणाचल प्रदेश .	7.3
मिजोरम . .	11.8
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5.32
लक्षद्वीप . .	0.88
जोड़ अखिल भारत	27712

Power generation to meet full demand

873. SHRI SANTOSH MITRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are making plans for power generation only to meet the 'restricted demand' and not to fulfil the real demand; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b) The Planning Commission, while formulating the Five Year Plans, takes into account the likely growth rates in different sectors of the economy "while estimating the likely demand -for power at the end of each plan period. However, due to various constraints such as shortage of financial resources, delays in delivery of •equipmemnts, shortages of materials, inadequacies in project management at the state level, etc., sometimes it becomes difficult to achieve the capacity additions as planned.

799 RS—4.

Conversion of substandard coal into CokSng coal

874. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: SHRI ASHWANI KUMAR; SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to a recent report of a revolutionary method of converting substandard coal into coking coal; and

(b) if so what the Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI GARGI SHANKAR MISHRA); (a) and (b) Coking property is inherent in coking coal and there is no proved method for upgrading substandard non-coking coal to coking coal. However, Central Fuel Research Institute, Dhanbad have developed a technique, namely oil agglomeration, by which low grade coking coal can be upgraded to high grade coking coal. Based on this technique developed by C.F.R.I., a 2 tonne per hour pilot plant is now operating at Lodna and a 10 tonne per hour demonstration plant is now under construction at Patherdih Washery Progress of these pilot plants is being watched by a committee set up by the Department of Coal. The commercialisation of this process could be considered on the basis of the successful operation of the demonstration scale unit.

मनेन्द्रगढ़ केन्द्रीय अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टर

875. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनेन्द्रगढ़ केन्द्रीय अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं ;